

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्य पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1. प्रभावी राजस्व घाटा	2.7	1.8	0.9	0.0
2. राजस्व घाटा	3.9	3.3	2.7	2.0
3. राजकोषीय घाटा	5.2	4.8	4.2	3.6
4. सकल कर राजस्व	10.4	10.9	11.2	11.5
5. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ ²	45.9	45.7	44.3	42.3

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमान के लिए अचल विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ तथा एमएसएस देनदारियाँ, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल हैं।

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन और ऊपर प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्षों के लिए चल लक्ष्य 2012-13 के बजट में किए गए 5.1 प्रतिशत की तुलना में 5.2 प्रतिशत की पूर्वानुमान में चूक दर्शाते हैं। तथापि, इस निष्पादन को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट और वैश्विक रूप से जारी अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में देखा जाना है। वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की गई दोहरा घाटा चुनौती ने नीतियों में परिवर्तन अनिवार्य बना दिया। मौजूदा वित्त वर्ष में सामना की गई चुनौतियों की तुलना में उपर्युक्त सारणी मध्यकालिक सुधार के रूप में सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन को दर्शाती है।

2. मध्यवर्षीय सुधार का जारी वैश्विक अनिश्चित आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना है, जिससे भारत का व्यापार प्रभावित हुआ। एक ओर मुख्य अर्थव्यवस्था में मांग घटने से निर्यात में कमी आयी, कच्चे तेल की उच्च और स्थिर कीमत के कारण व्यापार अन्तर बढ़ा। दूसरी ओर राजकोष बढ़ाने के उपाय किए जाने के कारण सरकारी व्यय और परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। राजकोषीय घाटा का स्थायी उच्च स्तर यद्यपि वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में अपेक्षित था, के कारण भी विभिन्न प्रकार के वृहत आर्थिक असंतुलन आए, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था और 2012-13 के दौरान तथा इसके बाद राजकोषीय घाटा में संभावित वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता हुई।

3. अतः वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान भारत में वृहत आर्थिक विश्लेषण ने वर्तमान खाता में घाटे की प्रवृत्ति, स्थायी मुद्रास्फीति, बचत दरों में गिरावट, निवेशों यहां तक कि खपत में गिरावट दर्शाया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के साथ-साथ मौद्रिक नीति को सख्त बनाने के उपायों के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस पृष्ठ भूमि में सरकार की राजकोषीय स्थिति कठोर दिखाई देने लगी। राजस्व के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद में मन्दी के कारण लक्ष्य की अल्प प्राप्ति का डर था जबकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने सरकारी व्यय पर दबाव डाला था।

4. तदनुसार सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु सरकार ने केलकर समिति का गठन किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राजकोषीय समेकन हेतु योजना की घोषणा की और आर्थिक विकास की पुर्नबहाली के लिए अनेक उपाय किए। इसके परिणामस्वरूप अनेक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने राजकोषीय घाटा के लिए अपने ही लक्ष्य को बेहतर बनाया जो आयोजना में घोषित 5.3 प्रतिशत की तुलना में 5.2 प्रतिशत है। इस निष्पादन को "निष्क्रिय" परिदृश्य में देखा जाना है, जो 6.1 प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा दर्शाया है यदि तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाएं।

5. केन्द्र को प्राप्त कुल निवल राजस्व में ₹63,857 करोड़ की राजस्व कमी की तुलना में राजकोषीय घाटे पर निष्पादन अधिक अतुलनीय है। आयोजना-भिन्न व्यय में ₹31,738 करोड़ की वृद्धि

की तुलना में राजस्व में यह कमी सब्सिडी में वृद्धि होने के कारण आयी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष में अन्तर बढ़ गया। अतः राजस्व घाटा बजट अनुमान 2012-13 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमान 2012-13 में 3.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन और व्यय पर नियंत्रण से सरकार ने 2012-13 का अंत सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत पर किया जो मध्यवर्षीय समीक्षा में घोषित 0.1 प्रतिशत से कम है।

6. राजकोषीय घाटे का सरकार के घटते संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना है। कम होते निर्यात और कम औद्योगिक विकास कर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में बजटीय लक्ष्य में चूक दर्शाते थे। केन्द्र को करों पर ₹28,956 करोड़ की निवल कमी अर्थव्यवस्था में आयी समग्र गिरावट के कारण हुई। इसी प्रकार कर-भिन्न राजस्व के कारण 2जी स्पेक्ट्रम बिक्री की खराब अनुक्रिया की वजह से ₹34,901 करोड़ की कमी आयी।

7. तथापि, सरकार ने विशेषकर विनिवेश से ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों पर बचे-खुचे संसाधनों को समाप्त करने का अभियान चलाया। विनिवेश पर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय में सचिवों की समिति ने नियमित रूप से समन्वय किया। इससे ने केवल सरकार के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिली अपितु बाजार को प्रोत्साहित करने हेतु सकारात्मक गति प्रदान करने में भी सहायता मिली। सक्रिय भूमिका से यह सुनिश्चित किया गया कि सरकारी प्राप्तियां यथासंभव बजटीय अनुमानों के आस-पास हो। इसके परिणामस्वरूप विनिवेश में बजट अनुमान के लक्ष्य ₹30,000 करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹24,000 करोड़ पर संशोधन किया गया।

8. साथ ही साथ सरकारी व्यय नियंत्रित करने और निजी निवेश हेतु पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करने और मौद्रिक नीति कम करने की उभरती दृष्टि से सरकार ने व्यय सीमित करने का कार्य शुरु किया। सरकार का कुल व्यय ब.अ. 2012-13 में ₹14,90,925 करोड़ की तुलना में घटकर संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹14,30,825 करोड़ हो गया। इस कमी को मुख्य सब्सिडी व्यय की पृष्ठभूमि में देखा जाना है जो बजट अनुमान 2012-13 में ₹1,79,554 करोड़ से बढ़कर संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹2,47,854 करोड़ हो गया। तथापि, ब्याज अदायगियों सहित दूसरे आयोजना-भिन्न व्यय में कमी आयी, जो बजट अनुमान 2012-13 में ₹3,19,759 करोड़ से घटकर संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹3,16,674 करोड़ रह गया।

9. वित्तीय पक्ष में दिनांकित प्रतिभूतियों से बाजार उधार वित्त वर्ष 2012-13 की पिछली साप्ताहिक उधार रद्द करके घटकर ₹12,000 करोड़ हो गयी। यह राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन करने हेतु सरकार की मंशा जाहिर करने में महत्वपूर्ण कदम था और इसे बाजार द्वारा सकारात्मक रूप में देखा गया। कुशल राजकोषीय प्रबंधन से सरकार ने घाटा अनुमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया, इसके द्वारा बाजार उधार में कटौती करने की संभावना दी गई। बाजार उधार में इस कटौती को गिरते विदेशी उधारों की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। निवल विदेशी उधार को ब.अ. 2012-13 के ₹10,148 करोड़ की तुलना में संशोधित कर सं.अ. 2012-13 में ₹2,214 करोड़

कर दिया गया। अल्पावधिक राजकोषीय हुंडियों से उधारों की राशि को ब.अ. 2012-13 के ₹9,000 करोड़ से बढ़कर सं.अ. 2012-13 में ₹29,000 करोड़ कर दिया गया।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

10. सरकार ने 2012-13 में मध्यावधि सुधार के साथ राजकोषीय समेकन का मार्ग चुना। राजकोषीय नीति 2013-14 की रूपरेखा किसी अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। राजकोषीय समेकन प्रक्रिया पर ध्यान वापस लाकर सरकार ने राजकोषीय घाटे को स.अ. 2012-13 के स.घ.उ. के 5.2 प्रतिशत से घटाकर ब.अ. 2013-14 में सं.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत करने हेतु कई उपाय आरंभ किए हैं। राजकोषीय घाटे में 0.4 प्रतिशत बिन्दु की कमी मुख्यतया राजस्व की वजह से आई है। जहां ब.अ. 2013-14 में व्यय स.घ.उ. के 14.6 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है, वहीं कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्वों में स.घ.उ. की क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की वृद्धि रही।

11. ब.अ. 2013-14 में राजस्व घाटा स.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह राजस्व घाटा 3.4 प्रतिशत के ब.अ. 2012-13 स्तर से मामूली रूप से कम है। तथापि, यह 3.9 प्रतिशत पर सं.अ. 2012-13 से काफी कम है। बढ़ते सब्सिडी बिलों की रोकथाम के लिए कई नीतिगत उपाय विशेषकर प्रगामी रूप से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को बाजार कीमतों से जोड़ने पर प्रगामी रूप से परिणाम उत्पन्न होंगे। ऐसी, प्रत्याशा है कि बेहतर व्यय प्रबंधन के साथ राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में गिरकर क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत हो जाएगा।

12. चूंकि राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण अनुपात पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में प्रदान किया जा रहा है, अतः सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे को देखा जाना उचित होगा। राजस्व खाते में ऊपर उल्लिखित अनुदान संघटक में विचार किए जाने के पश्चात ब.अ. 2013-14 में प्रभावी राजस्व घाटा स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। आगे 2014-15 में इसके गिरकर 0.9 प्रतिशत और 2015-16 में 0.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह राजस्व खाते में असंतुलन का ऐसा घटक है जिस पर व्यय प्रबंधन और राजस्व संवर्धन के जरिए गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

13. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सरकार की कुल देयताओं में भी हाल की तरह गिरावट वाली प्रवृत्ति देखी जाएगी। 2012-13 के अंत में सरकार की कुल देयता स.घ.उ. का 45.9 प्रतिशत अनुमानित है जो 2013-14 के अंत तक घटकर 45.7 प्रतिशत हो जाएगी। गिरावट की प्रवृत्ति के साथ यह 2014-15 में गिरकर 44.3 प्रतिशत और 2015-16 में 42.3 प्रतिशत होने की संभावना है। सरकार के ऋण-स.घ.उ. अनुपात में प्रगामी कमी से ब्याज भार में कमी आएगी और सरकार के लिए विशेषकर अवसंरचना विकास पर अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बिना व्यय करने की अधिक गुंजाइश उत्पन्न होगी।

14. सकल कर राजस्व के सं.अ. 2012-13 के स.घ.उ. के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2013-14 में 10.9 प्रतिशत (सं.अ. 2012-13 की तुलना में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि) होने का अनुमान है जो हालांकि 2007-08 में हासिल स.घ.उ. के 11.9 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। अर्थव्यवस्था के विकास दर की प्रवृत्ति वाले मार्ग में वापसी के साथ कर स.घ.उ. अनुपात के प्राप्त स्तर पर वापसी करना संभव होगा। मध्यावधि लक्ष्यों में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर संग्रहण 2014-15 में 11.2 प्रतिशत और 2015-16 में 11.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

15. इस विवरण में दर्शाई गई राजकोषीय समेकन की रूपरेखा सरकार के स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय को घटाकर संकट पूर्व अर्थात् 2007-08 स्तर तक लाने के सचेत प्रयास के साथ तैयार की गई है। सब्सिडियों के बदले में प्रतिभूतियों का निर्गम और राष्ट्रीकृत बैंकों को निर्गमित प्रतिभूतियों सहित 2007-08 के दौरान सरकार का कुल व्यय स.घ.उ. का 15.9 प्रतिशत रहा। 2008-09 में यह व्यय बढ़कर 17.3 प्रतिशत (सब्सिडियों के बदले में निर्गमित प्रतिभूतियों सहित) और सं.अ. 2010-11 में गिरकर 15.4 प्रतिशत हो गया। विकासात्मक क्षेत्र में व्यय के पुनः प्राथमिकीकरण और गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि की कटौती के साथ कुल व्यय के ब.अ. 2013-14 में गिरकर सं.घ.उ. का 14.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्यावधिक अनुमान में इसके और गिरकर 2014-15 में 13.7 प्रतिशत और 2015-16 में 13.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

ख. राजकोषीय संकेतकों को रेखांकित करने वाली मान्यताएं

1. राजस्व प्राप्तियां

(क) कर-राजस्व

16. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व उच्च आर्थिक वृद्धि के दम पर और कर सुधार उपायों के ठोस मेनु की सहायता से 2007-08 में अपने शीर्ष तक पहुंचा और 11.9 प्रतिशत के स्तर को छुआ। 2003-08 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान औसत वार्षिक कर वृद्धि 21.3 प्रतिशत थी जिसमें 2006-07 के दौरान वार्षिक कर वृद्धि 28.9 प्रतिशत पर अधिकतम रही। यह सुधार मुख्यतः प्रत्यक्ष कर के कारण हुआ जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर इस अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत थी। स.घ.उ. के संबंध में इस अवधि के दौरान कर राजस्व का उछाल लगभग 1.5% था।

17. उच्च कर-वृद्धि का यह रुझान वैश्विक आर्थिक संकट के कारण कम हुआ था और कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2008-09 में 10.8% तक और बाद में 2009-10 में 9.7% तक कम हुआ है। आर्थिक पुनर्प्राप्ति प्रारंभिक लक्षणों तथा 2010-11 में प्रेरक उपायों को आंशिक रूप से समाप्त करने के साथ, कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 10.2% तक बढ़ा है, जिसके साथ कर राजस्वों ने 27% की उच्च वृद्धि दर्शायी है। चूंकि प्रेरक उपाय मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर पक्ष की तरफ थे, आंशिक रूप से समाप्ति ने 2009-10 वास्तविक के मुकाबले 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में 40.7% की उच्च वृद्धि दर्शायी।

18. आर्थिक पुनर्प्राप्ति के लक्षण, तथापि 2011-12 में कम हुए, विशेषरूप से उत्तरार्ध में, जब 2011-12 के दौरान अर्थव्यवस्था ने 6.2% की वृद्धि दर्शायी। जबकि 2011-12 के पूर्वार्ध में कर वृद्धि 14% थी, उत्तरार्ध में कर वृद्धि केवल 11% थी जिससे 2011-12 में पूरे वर्ष के लिए 12.1% की कुल कर वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष करों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रभाव से, 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर 9.1% तक कम हो गया। प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2010-11 में 5.7% से 2011-12 में 5.5% तक कम हो गया, जबकि अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहा प्रत्यक्ष करों में, कमी मुख्य रूप से निगम कर से हुई जो 2010-11 में 22% की तुलना में 2011-12 में केवल 8% बढ़ी। इसके विपरीत, व्यक्तिगत आयकर 2010-11 में 13% की तुलना में 2011-12 में 18% तक बढ़ गया। अप्रत्यक्ष करों में, सीमा और उत्पाद शुल्क अपेक्षित आर्थिक विकास में कमी द्वारा प्रभावित हुए, 2011-12 के दौरान सेवा कर समग्र 37% तक बढ़ा। सकल कर राजस्व 2011-12 में बजट अनुमानों की तुलना में लगभग ₹43,000 करोड़ कम हो गए।

19. वर्तमान वर्ष के दौरान, पूर्वार्द्ध में सतत मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के कारण और साथ ही अनुमान से कम आर्थिक विकास के कारण, कर राजस्व पूर्वार्द्ध में अपेक्षित वृद्धि दर से कम बना रहा। तथापि, वर्ष के दौरान करों में निरंतर वापसी के संकेत देखे गये हैं। वर्ष के शेष भाग के दौरान संभाव्य राजस्व वृद्धि तथा प्रवृत्ति पर आधारित, कर राजस्वों के संशोधित अनुमान ₹39,575 करोड़ पर नियत किये गए हैं जो बजट अनुमानों से कम हैं। मुख्यतः ये ज्यादातर गिरावट अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्कों तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के कारण होती है। यद्यपि उम्मीद है कि सेवा कर बजटीय लक्ष्यों से बेहतर निष्पादन करेगी, इस संबंध में प्राप्त अतिरिक्त कर अन्य अप्रत्यक्ष करों की कमियों को आंशिक रूप से पूरा करेगा। वर्ष 2012-13 के दौरान, पूर्वानुमानित कर वृद्धि 2011-12 के वास्तविकों की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है तथा उम्मीद है कि सकल घरेलू उत्पाद में कर का अनुपात 10.4 प्रतिशत पहुंच जाएगा जो 2010-11 के स्तरों से आंशिक रूप से उच्च हैं।

20. वर्ष 2013-14 के लिए अनुमान वास्तविक आर्थिक समुत्थान तथा बजट 2013-14 में घोषित कर उपायों को ध्यानार्थ करते हुए किए गए हैं।

कर उपायों का ब्यौरा

21. उम्मीद है कि इन उपायों से कर राजस्व ब.अ. 2012-13 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पादन में कर अनुपात बजट 2013-14 में 10.9 प्रतिशत अनुमानित है। बजट अनुमान 2013-14 में संशोधित अनुमान 2012-13 की तुलना में 17 प्रतिशत की अधिक सामान्य कर वृद्धि अनुमानित है और शेष कर वृद्धि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों से सृजित होगी।

22. कर सुधार तथा कर प्रयास राजकोषीय समेकन की समग्र प्रक्रिया के अत्याधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। सद्दृढ़ और महत्वकांक्षी कर वृद्धि के बिना सरकार द्वारा तैयार की गई राजकोषीय घाटे को कम

करने की रूपरेखा को प्राप्त करना संभव नहीं है। जहां एक ओर कर अनुमानों का वास्तविक होना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इनका महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है ताकि सरकार अपेक्षित व्यय की सीमा से अधिक की सहायता लिये बिना राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बनायी गयी रूपरेखा को प्राप्त कर सके। समग्र रूप से, जहां कर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बढ़ने चाहिए, वहीं व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रगामी रूप से घटने चाहिए जब तक की राजकोषीय समेकन लक्ष्य की पूरी तरह प्राप्त न हो। जब अंतिम उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में कर अनुपात को संकट पूर्व स्तरों पर वापस लाना हो, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह राजकोषीय समेकन की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से ही होगा। जैसे सकल घरेलू उत्पादन के कर अनुपात में वृद्धि होती है, भावी सुधार अधिक क्रमिक होंगे तथा प्राप्त करना अधिक कठिन होगा। 2014-15 तथा 2015-16 वर्षों के लिए कर राजस्व की संभावना इसको ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जैसाकि उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कर अनुपात 2014-15 में 11.2 प्रतिशत और 2015-16 में 11.5 प्रतिशत होना अनुमानित है। इसका अभिप्राय 1.23 प्रतिशत की औसत उछाल से है जो वास्तविक परन्तु महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसको 17.5 प्रतिशत की औसत कर वृद्धि की आवश्यकता होगी जो बेहतर कर प्रयासों तथा कुछ एआरएम उपायों के जरिये संभव होगी।

(ख) राज्यों को अन्तरण

23. केंद्रीय करों की प्राप्तियों में राज्यों का भाग 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है जो सिफारिश करता है कि निवल प्राप्तियों का 32 प्रतिशत राज्यों को उनके भाग के रूप में अंतरित किया जाये। अनुमान अवधि तेरहवें वित्त आयोग की समय-सीमा से अधिक हो गई और नवगठित 14वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के एक वर्ष तक बनी रहेगी। यहां यहा माना गया है कि अनुमान अवधि के आगे राज्य का हिस्सा स्थिर रहेगा सिवाय इस बदलाव के कि उपलब्ध अवधारणा के लिए इससे बेहतर कोई अन्य आधार नहीं है। इस दस्तावेज में तैयार राजकोषीय आयोजना में यदि 14वां वित्त आयोग राज्य की हिस्सेदारी को बदलता है तो हमें भी इसे नए सिरे से तैयार करना होगा।

(ग) कर-भिन्न राजस्व

24. केन्द्र के कर-भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से सरकार की ब्याज तथा लाभांश प्राप्तियां केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं से प्राप्त आयों यथा विभिन्न एजेंसियों को केन्द्रीय पुलिस बलों की आपूर्ति करना, पासपोर्ट तथा वीजा आदि जारी करना, कंपनियों का पंजीकरण, पेटेन्ट तथा लाइसेंस फीस, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त रॉयल्टियों, पेट्रोलियम लाभ तथा दूरसंचार क्षेत्र से विविध प्राप्तियां शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार क्षेत्र की अन्य एकमुश्त प्राप्तियां जिन्हें कि केवल आंशिक तौर पर मूर्त रूप दिया गया है, के तथा ब्राड बैंड, वायरलेस स्पेक्ट्रम की नीमाली से ₹40,000 करोड़ बजटित किए गए हैं। तथापि, एक हद तक

लाभांश तथा लाभ कर उच्चतर प्राप्तियों द्वारा समायोजित किया गया। अन्य कर-भिन्न राजस्व में भी बजट अनुमानों की तुलना में किंचित वृद्धि देखी गई। समग्रतः 2012-13 में कर-भिन्न प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

25. वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान मार्च 2013 में दूरसंचार नीलामियों की अनुसूची को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे, जिसमें यह अपेक्षित था कि 2013-14 के शुरुआती दिनों में राशियां जमा हो जाएंगी। सरकार की ब्याज प्राप्तियों में रेलवे राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं। राज्यों से ब्याज प्राप्तियां समग्रतः कम हो रही हैं क्योंकि राज्यों से निवल ऋण 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मध्यस्थता हटाने के बाद विचारणीय रूप से घटे हैं। केन्द्र की लाभांश प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, (एक), भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों से तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। जहां उनके लाभ बढ़ने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों से प्राप्त लाभांश बढ़ना चाहिए, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों में सरकार के विनिवेश के कारण इसमें भी कमी आएगी। इसके विपरीत चूंकि बीएसईएल-III की सीआरएआर जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार बैंकों में इक्विटी डाल रही है इसलिए बैंकों से लाभांश लाभ में वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की भागीदारी में वृद्धि होने के कारण बैंकों से लाभांश में तेजी से वृद्धि होगी। इन मान्यताओं के साथ 2012-13 में केन्द्र का कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

26. उपर्युक्त मान्यताओं के अधिकांश अनुपालन के कारण वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए कर-भिन्न राजस्व परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। 2013-14 में बजटित कतिपय एकमुश्त प्राप्तियां 2014-15 और 2015-16 में उपलब्ध नहीं रहेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश के संबंध में सरकार की नीति उन्हें उनकी पूंजी परियोजनाओं में लाभ हासिल करने से रोकती है। तथापि, किसी ठोस पूंजी निवेश योजना के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने नकद अधिशेषों को लाभांश के तौर पर सरकार तथा अन्य श्रेयधारकों को दे देना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र में यह माना गया है कि 20 वर्षों के लिए जारी लाइसेंसों का नवीकरण अनुमान अवधि के दौरान किया जाना है। यह भी अपेक्षा है कि सेवा सुपुर्दगी की लागत के आधार पर उपभोक्ता प्रभारों को नियमित प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। पूर्वधारणाओं के आधार पर कर-भिन्न राजस्व 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 1.2% और 1.1% होना अनुमानित है।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

27. राज्यों से ऋणों की निवल वसूली में केंद्र सरकार द्वारा धीरे-धीरे मध्यस्थता न करने और ऋण समेकन व ऋण माफी योजना के कारण बारहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान कमी आई है। चूंकि राज्य सरकारों को और ऋण नहीं दिए जा रहे हैं; ये प्राप्तियां आगामी वर्षों में कम होंगी क्योंकि पुराने ऋण चुका दिए

जाएंगे। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से ऋणों की वापसी-अदायगी भी उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जो या तो रुग्ण है अथवा बीआईएफआर के जरिए पुनरुद्धार के अधीन है, से चूकों के कारण प्रभावित होगी। रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की ब्याज माफी अथवा ऋणों को बट्टे खाते डालने ने संभावित भविष्य की प्राप्तियों को कम कर दिया है। ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2012-13 के बजट अनुमान में ₹ 11,650 करोड़ अनुमानित थी। तथापि, इसे सं.अ. 2012-13 में उर्ध्वगामी संशोधित कर ₹ 14,073 करोड़ कर दिया गया था। ब.अ. 2013-14 में इसका ₹ 10,654 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए प्राप्तियों के इस घटक के ₹ 10,000 करोड़ पर बराबर रहने का अनुमान है क्योंकि सरकार निवल उधार देना प्रोत्साहित नहीं करेगी (राज्यों को विदेशी ऋण दिए जाने के बैक-टू-बैक प्रबंध के सिवाय)।

(ख) अन्य कर-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

28. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं। सरकार ने विगत दो वर्ष में अलग से संचित निधि के भीतर विनिवेश से प्राप्तियों का हिसाब रखने और इन्हें आयोजना परिव्यय के भीतर परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए इन्हें लगाने के अंतरिम उपाय के रूप में राष्ट्रीय निवेश निधि सृजित की थी। तथापि, इस वर्ष सरकार ने इस आशय के साथ एक अलग निधि, लोक लेखा के अंतर्गत एनआईएफ, सृजित करने का निर्णय लिया है कि विनिवेश प्राप्तियों को कतिपय अधिकृत प्रयोजनों हेतु ही लगाया जाएगा। इसे बड़े प्रगतिशील उपाय से ये प्राप्तियां सरकार के नियमित व्यय के निधियन हेतु उपलब्ध नहीं होंगी।

29. ब.अ. 2012-13 में ₹ 30,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में सं.अ. 2012-13 में इसे ₹ 24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसी कमी को विपरीत बाजार दशाओं के प्रति देखा जाना चाहिए और एक बार तो यह लगा था कि बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन सरकार की सक्रिय अवस्थिति ने इस खाते में प्राप्तियां जुटाने में ही नहीं बल्कि बाजार के पुनरुद्धार में भी सहायता की है। ब.अ. 2013-14 में यह अनुमान है कि विनिवेश से एनआईएफ के अंतर्गत ₹ 40,000 करोड़ की राशि एकत्रित होगी। इसके अतिरिक्त, 14,000 करोड़ गैर-सरकारी कंपनियों में सरकार के अवशिष्ट हिस्से के विनिवेश से प्रत्याशित हैं। इसके अतिरिक्त ₹ 1,814 करोड़ एनआईएफ में उपर्युक्त परिवर्तन के चलते विधटित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी से उपचित होने की संभावना है। अतः एव, ₹ 55,814 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जिसमें एनआईएफ के अंतर्गत ₹ 40,000 करोड़ और नियमित प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 15,814 करोड़ मिलेंगे। मध्यावधि कार्य योजना में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमशः ₹ 20,000 करोड़ और ₹ 15,000 करोड़ की सांकेतिक राशि ली गई है।

(ग) उधार-सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां

30. केंद्र सरकार के समग्र ऋण और देनदारियों का लगभग 92 प्रतिशत घरेलू ऋण और सिर्फ 8 प्रतिशत विदेशी ऋण होता है।

वर्ष 2012-13 में 2012-13 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 93.3 प्रतिशत के वित्तपोषण हेतु ₹ 4,79,000 करोड़ के निवल बाजार उधार की बजटीय व्यवस्था की गई थी। सकल राजकोषीय घाटे के शेष 6.7 प्रतिशत का वित्तपोषण करने के लिए विदेशी सहायता, राज्यों की भविष्य निधियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि जैसे वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की बजटीय व्यवस्था की गई थी। विदेशी ऋण और लघु बचतों से बजटीय व्यवस्था की तुलना में कम संग्रहण के परिणामस्वरूप और 5.2 प्रतिशत के संशोधित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने के लिए राजकोषीय हुंडियों की नीलामी से निवल उधार बढ़ाकर ₹ 20,000 करोड़ अर्थात् ब.अ. 2012-13 के ₹ 9,000 करोड़ से ₹ 29,000 करोड़ हो गई थी। तथापि, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2012-13 में बाजार उधार ₹ 12,000 करोड़ कम होकर ₹ 4,67,000 करोड़ रह गया। इस वर्ष का उधार कार्यक्रम उधारों के लिए पूर्व में घोषित कलेंडर के अनुरूप निर्बाध रूप से पूरा किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गमन की भारत औसत आय पिछले वर्ष की 8.52 प्रतिशत की तुलना में 8.36 प्रतिशत पर कम थी जबकि भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की 12.66 वर्ष से बढ़कर 13.50 वर्ष हो गई।

31. राजकोषीय समेकन के उपाय जारी रखने की सरकार की वचनबद्धता का पालन करते हुए 2013-14 में राजकोषीय घाटे के गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है। 2013-14 की कुल उधार आवश्यकता ₹ 5,42,499 करोड़ अथवा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था की गई है। राजकोषीय घाटे के लगभग 89% का वित्तपोषण करने के लिए ₹ 4,84,000 करोड़ के निवल बाजार उधार की बजटीय व्यवस्था की गई थी। वास्तविक अर्थों में, निवल उधार पिछले वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। सकल घरेलू उत्पाद के अर्थ में, हालांकि, इनकी गिरावट पिछले वर्ष 4.7 प्रतिशत की तुलना में 4.3 प्रतिशत रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है। वित्तपोषण के अन्य साधनों के अंतर्गत उधारों के 2013-14 के दौरान तुलनात्मक रूप नगण्य बने रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है। बाजार उधारों का बड़ा भाग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिदत्त होता है जो अपनी सकल जमाराशियों का लगभग 30 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बनाए रखता है।

32. 13.1 प्रतिशत बैंकों की सकल जमाराशियों में वर्षानुवर्ष वृद्धि (25 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) अनुमानित बाजार उधारों में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक होने से यह उम्मीद है कि 2013-14 के बजटीय बाजार उधार बाजारों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे और निजी निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार की कुल देनदारियों में विगत हाल में प्रवृत्तियों के जारी रहने से गिरावट भी दिखाई देगी। 2012-13 के अंत में सरकार की कुल देनदारी सकल घरेलू उत्पाद के 45.9 प्रतिशत के अनुमान से

गिरकर 2013-14 के अंत में 45.7 प्रतिशत रह जाएगी। हासकारी प्रवृत्ति जारी रहते हुए इसके गिरकर 2014-15 में 44.3 प्रतिशत और 2015-16 में 42.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार की ऋण सघउ अनुपात में प्रगामी गिरावट ब्याज भार को सहज बनाएगा और सरकार को अतिरिक्त उधारों का सहारा लिए बगैर खासकर अवसंरचना विकास में खर्च करने के लिए अधिक गुंजाइश की छूट देगा।

33. सकल घरेलू घाटे का प्रगामी रूप से 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत तक गिरना अनुमानित है। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में सरल राजकोषीय घाटे के और गिरकर 2014-15 में 4.2 प्रतिशत और 2015-16 में 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाजार उधार के वित्तपोषण को सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का लगभग 90 प्रतिशत मानते हुए, निवल बाजार उधार अगले तीन वर्षों में 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत, 2014-15 में 3.8 प्रतिशत तथा 2015-16 में 3.2 प्रतिशत तक काफी कम होने की संभावना है। सरकारी घाटे के कम होने से निजी निवेश तथा पूंजीगत अंतर्वहों के मिलने की ज्यादा गुंजाइश होगी। यह मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को कम करेगा और मौद्रिक नीति को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सुविधा प्रदान करेगा।

3. कुल व्यय

(क) राजस्व खाता

(i) आयोजना राजस्व व्यय

34. 11वीं योजना अवधि के दौरान सरकार का आयोजना राजस्व व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.2% के औसत स्तर पर रहा है तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक मंदी को रोकने के लिए किए गए प्रेरक उपायों के कारण, 12वीं योजना अवधि के दौरान समग्र आयोजना व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% था।

35. सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन के दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि आयोजना व्यय को इष्टतम स्तरों पर रखा जाए। 2008-09 के दौरान सरकार केवल राजकोषीय विस्तार का सहारा ले सकती थी क्योंकि यह कम राजकोषीय घाटे के आधार पर चल रही थी और अपने घाटे में किसी भी वृद्धि को वहन कर सकती थी। इस प्रकार की नीति का तब तक दोबारा पालन नहीं किया जा सकता जबतक राजकोषीय घाटा स्वीकार्य स्तर तक नीचे नहीं लिया जाता। जबकि प्रयास सरकार के अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए होने चाहिए, आयोजना व्यय को वहनीय स्तरों के अंतर्गत रहना होगा, कम से कम जब तक राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए।

36. वर्ष 2012-13 के दौरान, आयोजना व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक तर्कसंगत बनाया गया था और आयोजना व्यय के लिए 2012-13 का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% हो सकते हैं। 2013-14 के लिए आयोजना-व्यय 2012-13 के

बजट अनुमान के मुकाबले 6.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है जो 2012-13 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 29.4% बैठता है राजकोषीय लक्ष्यों तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आयोजना व्यय लक्ष्य अवधि के दौरान अनुमानित किया गया है।

(ii) आयोजना भिन्न-राजस्व व्यय

37. सरकार के गैर-आयोजना राजस्व व्यय में मुख्य रूप से इसका स्थापना व्यय, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय सब्सिडियां, राज्यों को दिए जाने वाली सांविधिक अनुदान तथा अन्य अवशिष्ट मद शामिल हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण गैर-आयोजना राजस्व व्यय 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% से 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.2% तक बढ़ गया है। उसके बाद, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न व्यय संबंधी सुधारात्मक उपायों के कारण यह 2013-14 के बजट अनुमान में 8.7% तक कम हो गया। गैर-आयोजना राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2012-13 में 9.17 लाख करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2013-14 में ₹9.93 लाख करोड़ होना अनुमानित किया गया है। गैर-आयोजना राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) ब्याज संबंधी भुगतान

38. सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय विस्तार के कारण, ब्याज संबंधी भुगतानों के बाद ने वैश्विक आर्थिक संकट को तेजी से बढ़ा दिया है। केन्द्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में, ब्याज संबंधी भुगतान 2007-08 में 38.9% से 2008-09 में 43.4% तक बढ़ गए तथा 2009-10 में 46.7% तक और अधिक बढ़ गए। चालू वर्ष में ब्याज संबंधी भुगतान केन्द्र को दिए जाने वाले निवल कर का 42.7% होगा। हाल की अवधि के दौरान ब्याज संबंधी भुगतान को प्रभावित करने वाले कारक 2011-12 के दौरान राजकोषीय कमी के साथ प्रेरक उपायों के कारण ऋण स्टॉक तथा तुलनात्मक रूप से मजबूत ब्याज दर व्यवस्था है जो काफी समय से अब तक आस्तित्व में रही है।

39. सरकारी घाटे के कम होने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों के साथ, यह आशा की जाती है कि ब्याज दर आगामी वर्षों में गिरेंगी। घाटे में कमी तथा ब्याज दरों में कमी से निजी क्षेत्र हेतु कम लागत पर संसाधन जुटाने के लिए गुंजाइश उत्पन्न होगी।

(ख) रक्षा सेवाएं

40. राजस्व खाते में रक्षा व्यय में मुख्यतः रक्षा सेवाओं के वेतन व्यय तथा उनके प्रचालनात्मक व्यय शामिल होते हैं। रक्षा राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹1.09 लाख करोड़ तथा बजट अनुमान 2013-14 में 1.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। लक्ष्य अवधि के दौरान रक्षा राजस्व व्यय 7% बढ़ना अनुमानित है।

(ग) पेंशन

41. केन्द्र सरकार के पेंशन संबंधी भुगतानों पर व्यय में रक्षा एवं सिविल दोनों की पेंशनें शामिल हैं। सामान्य संदर्भ में पेंशन संबंधी भुगतान संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹63,836 करोड़ तथा बजट-अनुमान 2013-14 में 70,726 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार का पेंशन संबंधी भुगतान वेतन व्यय की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च सेवा निवृत्तियों तथा वर्धित आयु प्रत्याशा के कारण पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तदनुसार विगत रुझान को ध्यान में रखते हुए सरकार का पेंशन व्यय 10% बढ़ना अनुमानित किया गया है।

(घ) राज्यों को दिया जाने वाला आयोजना-भिन्न अनुदान

42. राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-भिन्न अनुदानों में वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानें शामिल हैं। आयोजना-भिन्न अनुदान संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹57,901 करोड़ तथा बजट अनुमान 2013-14 में ₹76,981 करोड़ अनुमानित किए गए हैं। बजट अनुमान 2013-14 में सीएसटी की हानि के लिए राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति भी शामिल है जो जीएसटी को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच करार हेतु महत्वपूर्ण है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा इस तथ्य को कि सीएसटी क्षतिपूर्ति 2014-15 में भी जारी रहेंगी, इसे ध्यान में रखते हुए 2014-15 के लिए अनुमान लगाया गया है।

43. वर्ष 2015-16 में आयोजना-भिन्न अनुदान 2014-15 के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ा दी गई है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। सामान्यतः वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अधिकतर अनुदान प्रदान की जाने वाली अवधि के दूसरे वर्ष से दिए जाने संस्तुत किए जाते हैं ताकि राज्य सरकारों के लिए सुविधाजनक प्रारंभिक अवधि सुनिश्चित की जा सके। इन पूर्वानुमानों के आधार पर आयोजना-भिन्न अनुदान 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% तथा 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% अनुमानित किए गए हैं।

(ङ) मुख्य सस्त्रियां

44. बजट अनुमान 2012-13 में ₹1,79,554 करोड़ के मुकाबले संशोधित अनुमान 2012-13 में मुख्य सस्त्रियां बढ़कर ₹2,47,854 करोड़ हो गई है। वृद्धि का मुख्य हिस्सा पैट्रोलियम सस्त्रियों की तरफ से है जो बजट अनुमान 2012-13 में ₹43,580 करोड़ से बढ़कर संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹96.880 करोड़ हो गया है, बजट अनुमान 2012-13 में बजटित मुख्य सस्त्रियां ₹2,20,972 करोड़ की हो गई है। संशोधित अनुमान 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 प्रतिशत की कुल सस्त्रियां 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बजटित की जानी है।

45. राजकोषीय समेकन की दृष्टि से मुख्य सस्त्रियां आत्यन्तिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और अपने राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सरकार की सफलता निर्धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की कोशिश इस मामले को दोहरे रूप से

सुलझाने की होगी, पहले कुल सस्त्रियां वहनीय सीमा के भीतर ही बनी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सस्त्रियों युक्त वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण की नीति पर बनी रहेगी। इससे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सस्त्रियों के बेहतर तौर लक्षित करने के लिए एक समुचित प्रणाली को अमल में लाना अत्यन्त आवश्यक है।

46. सस्त्रियों को लक्षित करने के लिए सरकार ने यूआईडी प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए आधार से जुड़े बैंक खातों में लाभानुभोगियों को दिए जाने वाले लाभों से सीधे उनके खातों में जमा कराने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है। यद्यपि अभी तक स्कीम प्रायोगिक स्तर पर है तथा अभी इसके तहत सीमित जिलों को ही कवर किया जा रहा है। एक बार यह प्रयोग सफल होने तथा संतोषप्रद पाए जाने पर सभी लाभों के विभिन्न अन्तरणों की यह प्रणाली राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू कर दी जाएगी। चूंकि यह प्रणाली यूआईडी प्लेटफार्म पर आधारित है, इसलिए उसी दिन से डुप्लीकेट लाभार्थियों तथा गैर-मौजूद लाभार्थियों को अन्तरण रोकना सुनिश्चित किया जा सकेगा। यहां तक कि आने वाले समय में इससे अर्हता मामलों का समाधान भी आसानी से किया जा सकेगा।

47. मूल्यन के मामले खासकर पैट्रोलियम क्षेत्र में सबसे अहम वस्तु जो राजकोषीय समेकन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, डीजल है। डीजल मूल्य निर्धारण की मूल समस्या जो सरकार झेल रही है, वह यह है कि मूल्य सुधार में जरा सी देर अगले मूल्य सुधार की जरूरत को और भी गहरा और तीक्ष्ण बना देती है और स्थिति और भी जटिल होती जाती है। यह स्थिति उच्च सस्त्रियों और प्रशासित मूल्यों में लोचनीयता के दुष्प्रकार को जन्म देती है। इस मामले के समाधान के लिए प्रति लीटर में पांच रुपए की पर्याप्त मूल्य वृद्धि के बाद सरकार ने तेल विपणन कम्पनियों को बार-बार लघु मूल्य सुधार लागू करने की अनुमति दी हुई है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता मूल्य बढ़ने से आहत भी अनुभव न करे क्योंकि यह मूल्यवृद्धि छोटी ही होगी और इसी के साथ यह वास्तविक विनियंत्रण की दिशा में सरकार को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा मुद्रास्फीति में डीजल मूल्य की वृद्धि का प्रभाव न्यूनतम होगा। यदि तेल क्षेत्र में कोई अन्तर्राष्ट्रीय आयात न हो तो आशा की जा सकती है कि एक या दो वर्षों में सरकार डीजल को पूरी तरह से वि-नियंत्रित कर सकेगी।

48. उर्वरकों में, पीएंडके क्षेत्र में पोषक आधारित सस्त्रियों प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है। अब जरूरी यह है कि यूरिया के तत्काल सुधार के लिए कतिपय मूल्यन सम्बन्धी सुधार किए जाएं। यह सिर्फ सस्त्रियों बिल के आकार की दृष्टि से जरूरी नहीं है अपितु एनपी और के पोषकों के सन्तुलित उपयोग की दृष्टि से भी अनिवार्य है। दीर्घ आवधिक संदर्भ में सरकार उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि की दिशा में काम कर रही है जोकि आयात पर हमारी निर्भरता को घटाने में मदद करेगा और मूल्यों को ज्यादा स्थिर रखेगा।

49. आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत के साथ खाद्य सस्त्रियों प्रणाली को व्यापक रूप से नए सिरे से जांचे

जाने की जरूरत होगी। कानून लागू होने के साथ सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण, सुपुर्दगी श्रृंखला के बेहतर अनुगमन, एफसीआई तथा अन्य सम्बंधित सुधारों से जुड़े अन्य निकायों की प्रशासनिक लागतों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

50. जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है अभिकेंद्रित सब्सिडी सुधारों के बिना राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया करीब-करीब असंभव ही होगी। मुख्य सब्सिडियों पर साकार से व्यय के 2013-14 में 2% सकल घरेलू उत्पाद के 2% से 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% तथा 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6% तक नीचे आने की आशा है।

ख. पूंजी परिव्यय

51. संशोधित अनुमान 2012-13 में सरकार के कुल पूंजी परिव्यय के ₹1,67,753 करोड़ का अनुमान है जिसके बजट अनुमान 2013-14 में ₹2,29,129 करोड़ तक बढ़ने की आशा है इसमें से संशोधित अनुमान में ₹85,814 करोड़ का आयोजना खर्च होने का अनुमान है जिसके बजट अनुमान में ₹1,12,062 करोड़ तक बढ़ने की आशा है संशोधित अनुमान में आयोजना भिन्न पूंजी व्यय के ₹81.939 करोड़ होने का अनुमान है और 2013-14 में इसे ₹1,17,067 करोड़ तक बजटित किया गया है।

52. आयोजना-भिन्न पक्ष में पूंजी व्यय के प्रमुख भाग में रक्षा पूंजी व्यय है। संशोधित अनुमान 2012-13 में रक्षा पूंजी व्यय के ₹69,579 करोड़ होने का अनुमान है तथा उम्मीद है कि बजट अनुमान 2013-14 में यह बढ़कर ₹86,741 करोड़ हो जाएगा, अनुमानवधि के दौरान रक्षा पूंजी व्यय के 9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है जो कि केन्द्र के संसाधनों पर अन्य मांगों तथा समग्र संसाधन उपलब्धता के अनुरूप है।

53. भारत सरकार के आयोजना व्यय में मुख्यतया सकल रेल व्यय को सकल बजटीय समर्थन, सरकारी कम्पनियों तथा बैंकों में राष्ट्रीय राजमार्ग निवेशों तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को ऋण आदि में शामिल हैं। चूंकि समग्र प्रयासों से सरकार के राजस्व घाटे को कम करना है लिहाजा यह जरूरी हो जाता है कि समग्र योजना व्यय के दायरे में पूंजी घटकों पर व्यय राजस्व घटक पर व्यय की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़े। 2013-14 में आयोजना पूंजी व्यय कुल आयोजना व्यय का 20.2 प्रतिशत बजटित किया गया है और वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में इसके कुल आयोजना व्यय से क्रमशः 21% तथा 21.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

ग. वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लिए राजकोषीय संभावना

54. वर्ष 2012-13 का बजट सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% राजकोषीय घाटे के अनुमान के साथ तब प्रस्तुत किया गया था जब आर्थिक वृद्धि में सुधार के संकेत दिख रहे थे। जब 2012-13 का बजट पेश किया गया तब बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में 2011-12 के दौरान लगभग ₹31,000 करोड़ की कमी कर प्राप्तियों में थी। 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटे

के लिए संशोधित अनुमान बजट अनुमान 4.6 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2011-12 की राजकोषीय चूक 2012-13 में पुनः दोहरायी जाने वाली है, इसके पूर्वार्द्ध में प्रत्याशित आर्थिक वृद्धि से कम विकास और कर राजस्व में कमी दिख रही है। इसी प्रकार पेट्रोलियम सब्सिडी खाते पर पेट्रोलियम उत्पादों की कम वसूलियों में वृद्धि हुई है।

55. सरकार ने जटिल राजकोषीय स्थिति को गंभीरता से लिया है और मौजूदा राजकोषीय स्थिति के आकलन और चालू वर्ष में सरकार अपने राजकोषीय लक्ष्य को हासिल कर सके और इसी के साथ भविष्य के राजकोषीय समेकन की रूपरेखा सुझाने के लिए सरकार ने डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने संसाधनों की स्थिति और संसाधनों पर मांगों का विश्लेषण किया और सरकार के संसाधनों की वृद्धि संबंधी कई उपायों की स्थिति, सब्सिडी में व्यय को घटाने तथा योजना व्यय के यौक्तिकीकरण के संबंध में कई सिफारिशों की हैं।

56. केलकर सामिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राजकोषीय समेकन की एक रूपरेखा घोषित की और 2012-13 के दौरान किसी संभावित राजकोषीय चूक से बचने के क्रम में कई उपाय किए। वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया और आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए एक चाक-चौबंद कार्यक्रम शुरू किया गया। व्यय विभागों तथा मंत्रालयों को राजकोषीय विवेक और किफायत बरतने की सलाह दी गई। केलकर, समिति का मानना था कि किसी सुधारात्मक उपाय की किसी भी अनुपस्थिति से केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.1 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उसका सुझाव था कि केन्द्र सरकार को इसके द्वारा संस्तुत सिफारिशों को लागू करना चाहिए और अपने राजकोषीय घाटे को 5.3 प्रतिशत तक सीमित करना चाहिए। अपनी राजकोषीय रूपरेखा में सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 2012-13 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2012-13 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान स.घ.उ. का 5.2 प्रतिशत है।

57. वर्ष 2013-14 के लिए तैयार की गई राजकोषीय नीति सरकार द्वारा इस संबंध में पहले से घोषित रूपरेखा के अनुरूप है। इस तरीके को बजट में शामिल करने के साथ ही सरकार ने राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के प्रति अपनी विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता दर्शायी है। सरकार के राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटों के लक्ष्य सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन की उपर्युक्त रूपरेखा के ही अनुरूप हैं। यह रूपरेखा इसलिए तैयार की गई है जिससे कि इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके और इसके साथ ही सरकार की विश्वसनीयता तथा राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के प्रति उसकी वचनबद्धता को स्थापित किया जा सके। इस अध्याय में ऊपर स्पष्ट की गई रूपरेखा की मुख्य बातों को पूरा करने में कई सघटकों की मान्यताएं बाधक हैं।